# TRAI DECRIMINALIZATION NOTIFICATION AMENDMENT

As part of the ongoing exercise to reform governance, it has been decided to undertake a detailed exercise to decriminalize minor offences under the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995.

In this regard, a decision has been taken in this Ministry to delete the entire provision of section 16, section 17 and section 18 under chapter - IV of the Cable Television Networks (Regutation) Act, 1995, captioned as "OFFENCES PENALTIES". Proposed amendments is annexed at Annexure-I.

The earlier proposed addition in the said Act circulated / published vide this Ministry's communication number N-45001/6/2019-DAS (Pt) dated 20th March, 2020 regarding Treatment of Violations under section 5 (Programme code) and Section 6 (Advertisement code) under section 16 shall now be shifted to under section 11 as its sub-Section (1). All other proposed modifications shall remain unchanged.

Comments of general public and all the stakeholders concerned are therefore invited latest by 15th August, 2020.

The Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 may be referred to on this Ministry's official website https://mib.gov.in.

## AMENDMENT PROPOSED FOR THE DECRIMINALIZATION OF MINOR OFFENCES UNDER THE CABLE TELEVISION NETWORKS (REGULATION) ACT, 1995.

**SECTION 11: Punishment for contravention of provisions of this Act Power to seize equipment used for operating cable television network**

1) **any violation of the Programme Code under Section 6 shall invite one or more of the following actions by the Central Government:**

# ट्राई गैर–अपराधीकरण अधिसूचना संशोधन

कामकाज में सुधार के लिए चल रही कवायद के तहत केवल टेलीविजन नेटवर्क (नियमन) अधिनियम, 1995 के तहत मामूली अपराधों को कम करने के लिए एक विस्तृत अभ्यास करने का निर्णय किया गया है।

इस संबंध में इस मंत्रालय में केबल टेलीविजन नेटवर्क (नियमन) अधिनियम, 1995 के अध्याय –IV के तहत धारा 16, धारा 17 और धारा 18 के पूरे प्रावधान को हटाने का निर्णय लिया गया है, इसे 'अपराध दंड' शीर्षक दिया गया है। प्रस्तावित संशोधनों को एनेक्सचर–1 में शामिल किया गया है।

इस मंत्रालय के संचार संख्या एन–45001/6/2019–डीएएस (पीटी) दिनांक 29 मार्च 2020 के तहत धारा 16 के तहत धारा 5 (कार्यक्रम कोड) और धारा 6 (विज्ञापन कोड) के तहत उल्लंघन के उपाय के बारे में परिचालित/प्रकाशित उक्त अधिनियम में पूर्व प्रस्तावित जोड़ को अब धारा 11 के तहत उसकी उप धारा (1) के रूप में स्थानांतरित किया जायेगा। अन्य सभी प्रस्तावित संशोधन अपरिवर्तित रहेंगे।

इसलिए 15 अगस्त 2020 तक आम जनता और सभी संबंधित हितधारकों की टिप्पणियां आमंत्रित की गयी।

केबल टेलीविजन नेटवर्क (नियमन) अधिनियम 1995 के लिए इस मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट https://mib.gov.in का उल्लेख किया जा सकता है।

**केबल टेलीविजन नेटवर्क (नियमन) अधिनियम, 1995 के तहत छोटे अपराधों के गै–अपराधीकरण के लिए प्रस्तावित संशोधन।**

**धारा 11ः संचालित केबल टेलीविजन नेटवर्क के लिए उपयोग किये जाने वाले उपकरणों को जब्त करने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए सजा**

1) **धारा 6 के तहत कार्यक्रम कोड का कोई भी उल्लंघन केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित कार्रवाईयों में से किसी एक को आमंत्रित करेगाः**

# SCAT DIARY

*Here's a listing of some of the major events connected with our industry.*

**AUGUST 2020**

Aug18 :**THAILAND IN VIEW**
Virtual Seminar
Email : adela@avia.org / victor@avia.org
URL :https://avia.org/all_events/thailand-in-view/

**SEPTEMBER 2020**

Aug18: **FUTURE OF VIDEO INDIA 2020**
Virtual Seminar
Email :adela@avia.org / victor@avia.org
URL :https://avia.org/all_events/future-of-video-india-2020/

Aug18: **AVIA SATELLITE INDUSTRY FORUM (SIF)**
Virtual Conference
Email : adela@avia.org / victor@avia.org
URL : https://www.aviasif.com

**BI2020**
BROADCAST INDIA • MUMBAI
29 - 31 October 2020

**OCTOBER 2020**
Oct 29-31: **BROADCAST INDIA 2020**
Tel. : +91 22 6216 5303 / 6216 5313
+91 22 6216 5312
Email : bis@nm-india.com
URL : http://www.broadcastindiashow.com/

The 29th SCAT INDIA 2020

**SCAT2020**
SAT & CABLE TV INDIA • MUMBAI
29 - 31 October 2020

**OCTOBER 2020**
**Oct. 29-31: SCAT INDIA 2020**
Email : varun.gaba@nm-india.com
scat.sales@scatmag.com
URL : www.scatmag.com/scatindia

# TRAI NOTIFICATION

**a) Issuing advisory, or censure, or warning**
**b) Prohibition of transmission of offending programme;**
**c) Apology scroll specifying the date and time;**
**d) Prohibition of transmission of the channel for a period not exceeding thirty days;**
**e) In instances where actions referred to in clause (ii) and (iv) above are repeated five times or more for a channel, the Central Government may cancel the permission granted to the channel after giving due opportunity to the channel.**

* If any authorised officer has reason to believe that the provisions of section 3, section 4A, section 5,section 6, section 8, section 9, section 10, section 19 or section 20 have been or are being contravened by any cable operator, he may seize the equipment being used by such cable operator for operating the cable television network:
Provided that the seizure of equipment in case of contravention of sections 5 and 6 shall be limited to the programming service provided on the channel generated at the level of the cable operator.]

**Deletion of Section 16, Section 17 & Section 18 in view of decriminalization of minor offences ■**

** Earlier proposed amendments in this section circulated on Ministry's website are under consideration*

**ए) सलाहकार या सेंसर या चेतावनी जारी करना**
**बी) आपत्तिजनक कार्यक्रमों के प्रसारण पर रोक**
**सी) तिथि और समय निर्दिष्ट करते हुए माफी स्क्रॉल**
**डी) चैनल के प्रसारण पर प्रतिबंध, जो कि 30 से अधिक दिनों की नहीं होगी**
**ई) ऐसी हालत में जहां किसी चैनल के लिए ऊपर दिये गये खंड (ii) और खंड (iv) का उल्लंघन पांच या इससे अधिक बार दोहराया जाता है तो केंद्र सरकार चैनल को उचित अवसर देने के बाद चैनल को दी गयी अनुमति को रद्द कर सकती है।**

* यदि किसी प्राधिकृत पदाधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि धारा 3, धारा 4ए, धारा 5, धारा 6, धारा 8, धारा 9, धारा 10, धारा 19 या धारा 20 के प्रावधान का किसी भी केबल ऑपरेटर द्वारा उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है तो वह केबल टीवी नेटवर्क के संचालन के लिए ऐसे केबल ऑपरेटरों द्वारा उपयोग किये जा रहे उपकरणों को जब्त कर सकता है:
बशर्ते कि धारा 5 और 6 के उल्लंघन के मामले में उपकरणों की जब्ती केबल ऑपरेटर के स्तर पर चलाये चैनल पर प्रदान की गयी प्रोग्रामिंग सेवा तक सीमित होगी।

**छोटे अपराधों के गैर-अपराधीकरण के मद्देनजर धारा 16, धारा 17 और धारा 18 को हटाना।**

** पहले मंत्रालय की वेबसाइट पर भेजे गये इस खंड में प्रस्तावित संशोधन विचाराधीन हैं।*